मध्य प्रदेश की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी मझौली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

1142. **ठाकुर जगतपाल सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मझौली और बड़ी ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें केवल इसलिये स्वीकृत नहीं किया गया है कि मध्य प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों से पानी के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं कर सका ;

(ख) इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रयास किये हैं, और

(ग) इन विवादों को कब तक सुलझाये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को घाटा

1143. **ठाकुर जगतपाल सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कपड़ा मिलों में हुए घाटे के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सुधार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद भी इन मिलों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के आधुनिकीकरण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान एन० टी० सी० (मध्य प्रदेश) लि० के अन्तर्गत वस्त्र मिलों में हुई अंनतिम नकद हानि 15.28 करोड़ रु० थी जो कि वर्ष 1987-88 के दौरान 17.35 करोड़ रु० थी।

(ग) और (घ) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण पर 29.78 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी। यह राशि घाटों में कमी करने की दृष्टि से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। एन० टी० सी० (म०प्र०) के अन्तर्गत मिलों में लगातार घाटा होते रहने के लिए जो प्रमुख कारण हैं, उनमें शामिल हैं, अधिक श्रमिक बल, रुई और अन्य अन्तर्विष्ट साधनों जिनमें मजदूरियां तथा वेतन आदि शामिल हैं, की कीमतों में तीव्र वृद्धि।

Lifting of ban on felling of trees in Gujarat

1144. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Gujarat Government has recently lifted the ban on felling of trees in the State; and

(b) if so, what is the Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI SUMATI